to know whether any assistance for starting agro-industries is given ? Would they provide special funds for Agro-Industries which are under the control of the State agricultural departments ?

SHRI SIDDHESHWAR PRASAD The hon Member is not correct During the Fourth Plan the outlay for Agro Industries was Rs 28 crores Because the Agro-industries Corporations in different States were not able to spend this amount, the Planning Commission had to review the position and bring down the outlay

SHRI K SURYANARAYANA My main question is

MR SPEAKER If you ask a brief and precise question, it is easy to understand One is lost in such a long question

SHRI K SURYANARAYANA The agro-industries corporations have no finances Will they ask the State Governments to see how best to utilise assistance given from the Centre ?

SHRI SIDDHESHWER PRASAD From time to time we have been trying to expedite matters The Development Commissioner, small scale industries organisation has prepared 75 schemes and we are circulating them to agro-industries corporation for further action

श्री शशि भूषण : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हू जैसे सरकार की नीति बन गयी है कि छोटी कारे पब्लिक सेक्टर में नही बनेगी तथा प्रायरेन्टी सेक्टर से भी नही रहेंगी, उसी तरह क्या छोटे ट्रैक्टर भी पब्लिक सैक्टर मे जल्दी नही बनने वाले हैं, या उसके लिये भी वही कहेंगे कि वह पब्लिक सैक्टर मे नही बन सकेंगे ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : जहा तक ट्रैक्टर का सवाल है मेरा ख्याल है माननीय सदस्य को मालूम होगा कि एच० एम० टी० ने ट्रैक्टर बनाने का एक कारखाना स्थापित किया है । अभी उसमे असेम्बलेज का काम शुरू किया है । बाद मे बनेंगे ट्रैक्टर ।

श्री शशि भूषण कब से बनेंगे ?

अध्यक्ष महोदय छोडिये बन जायेंगे ।

Shortage of Raw Materials in Industriese in Bihar

*966 SHRI SUKHDEO PRASAD VERMA Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT be pleased to state

(a) whether the Central Government are aware that many industries in Bihar are facing closure because of short supply of raw materials ,

(b) whether some States, like Assam and Madhya Pradesh have banned the movement of raw materials resulting in acute shortage in Bihar , and

(c) if so, the reaction of Central Government thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI SIDDHESHWAR PRASED) (a) There is a general shortage of steel and certain other industrial raw materials which has affected industrial production throughout the country

(b) No, Sir

(c) Does not arise

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि बिहार एक तो औद्योगिक क्षेत्र मे पिछडा हुआ है ही, तो कितने उद्योग ऐसे हैं जो कच्चा माल न मिलने के कारण प्राय: बन्द हो गये हैं ? और बिहार मे कितने उद्योग चल रहे हैं जिनको सामान की कमी के कारण खतरा पैदा हो गया है ?

दूसरे मैं यह जानना चाहता हू कि क्या सरकार को इस बात का पता है कि इस्पात और अन्य साधनो के अलावा छोटे उद्योगो को नान-कोकिंग कोल का दाम बढ जाने के कारण तथा वैगनो की कमी के कारण सामान नही पहुच पाता है जिसके चलते हुए वह कारखाने खतरे मे पडे हुए हैं । तो मैं सरकार से जानना

चाहता हूं कि जो उद्योग बन्द हो गये हैं उन उद्योगों को सामान की कमी की पूर्ति के लिये सरकार कौन से उपाय करने जा रही है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उद्योगों को कच्चा माल न मिलने के कारण और कच्चे माल का दुरुपयोग होने के कारण उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : माननीय सदस्य ने कई बातें एक साथ पूछी है। जहां तक कच्चे माल की कमी के कारण उद्योग धन्धों के बन्द होने का सवाल है, बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार यह बात सही नही है। यह ठीक है कि कच्चे माल की कमी है और इसकी वजह से न केवल बिहार मे बल्कि दूसरे सूबों मे भी उद्योगो के उत्पादन मे कमी आई है और सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि यहा से कच्चा माल अधिक मिल सके और उद्योगो को दिया जाय। जहा तक इस्पात या दूसरे माल का सवाल है जो इंजीनियरिंग या दूसरी इडस्ट्रीज मे काम आते है, उनको विदेशों से मगा कर उद्योगो को दिया जायेगा।

दूसरी बात माननीय सदस्य ने वितरण के सम्बन्ध मे कही। हम बिहार सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करेंगे कि वह वितरण के सम्बन्ध मे सुधार लाने की कोशिश करे।

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : मैंने इसके साथ एक सवाल और रक्खा था। मै पुनः उसको दोहराता हू। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नान-कोकिंग कोल के मूल्य में बहुत अधिक वृद्धि हो जाने के कारण और वैगनों की कमी के कारण सामान नही पहुंचता है ? इस कारण और कच्चे माल की कमी के कारण कारखाने बन्द हो रहे हैं ? क्या सरकार इस कमी की पूर्ति करने के लिये जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करना चाहती है ? दूसरी बात यह.....

अध्यक्ष महोदय : एक सवाल का जवाब आने दीजिये।

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : फिर आप कहेंगे कि तुम्हारे दो सवाल पूरे हो गये और आगे सवाल करने का अधिकार तुमको नही है। तब फिर मैं क्या करूंगा ? इसलिये एक प्रश्न मे ही दो तीन प्रश्न पूछने आवश्यक हो जाते है।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से आप एक सवाल में दस सवाल कर देंगे तो मुश्किल हो जायेगी।

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि बिहार मे जो उद्योग धन्धे कच्चे माल की कमी के कारण बन्द हो गये हैं या बन्द होने की स्थिति मे है उनको जल्द से जल्द कच्चा माल मिले, इसके लिए सरकार कोई कार्रवाई करने जा रही है या नहीं ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मैंने अभी बतलाया कि जहा तक अखिल भारतीय स्तर पर कच्चे माल की कमी का सवाल है, हम लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि उद्योगो को और कच्चा माल मिल सके। जो कच्चा माल इस देश में नहीं मिलता, जैसे इस्पात, उसको हम बाहर से मंगाने की कोशिश कर रहे है ताकि वह उद्योगों को मिल सके। लेकिन बिहार सरकार से जो सूचना मिली है उसके अनुसार यह बात नही है कि बिहार का कोई उद्योग कच्चे साल की कमी के कारण बन्द हो गया है। उत्पादन में कमी जरूर हुई है। हम इसके लिये कोशिश कर रहे है कि कच्चा माल मिले।

जहां तक वैगनों का सवाल है, यह तो रेलवे मंत्रालय ही बतला सकता हैं कि वैगनो की कमी की वजह से कच्चा माल पहुचने में दिक्कत हो रही है या नही। अगर हो रही है

तो इसके बारे मे आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिये ।

Payment of pay and Allowances to Temporary Government Employees who participated in 1968 Strike

*967 SHRI S M. BANERJEE Will the PRIME MINISTER be pleased to state

(a) whether a final decision has since been taken regarding payment of pay and allowances to those temporary Central Government employees who participated during 1968 strike in accordance with the judgment of the Supreme Court

(b) if not, the reason for this abnormal delay ,

(c) whether there is a growing discontentment among the Central Government employees over this abnormal delay in taking a final decision, and

(d) if so, the reaction of the Government ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAM NIWAS MIRDAA) (a) to (d) A statement is laid on the table of the House

Statement

It is presumed that the Member is referring to the Judgment of the Supreme Court in Civil Appeal No 1706(N) of 1971 dated the 18th February, 1972 If so, the action already taken in pursuance of that judgment and the further action proposed to be taken were indicated in the replies given in this House to Unstarred Question No 2623 and Starred Question No 776 by the same Member, on the 12th April 1972 and the 10th May, 1972, respectively

The relevant Rule of the Central Civil Service (Temporary Service) Rules, 1965 which was discussed in the Supreme Court Judgment, applies, besides the employees who went on strike to other temporary employees also The cases of the temporary employees who went on strike in 1968 and were later on reinstated cannot, therefore, be dealt with in isolation The matter was also raised by the Staff Side at the last meeting of the National Council set up under the Joint Consultative Machinery, held on the 24th March, 1972 The implications of the Supreme Court Judgement in relation to all temporary employees are being examined also taking in th account the discussions held in the National Council meeting As the House would appreciate, this is a matter which would require very careful examination before a final decision is taken

SHRI S M BANERJEE May I draw your kind attention to the statement? It says

> "It is presumed that the Member is referring to the Judgment of the Supreme Court in Civil Appeal No 1706(n) of 1971 dated the 18th February, 1972 If so, the action already taken in pursuance of that judgment and the further action proposed to be taken were indicated in the replies given to this House to Unstarred Question No 2623 and Starred Question No 776 by the same member ' etc.

In reple to part (b), he could have said, please discuss with me in the lobby

SHRI RAM NIWAS MIRDHA Read the next para also

SHRI S M BANERJEE Yes It says,

> "The implications of the judgment in relation to all temporary employees are being examined, also taking into account the discussions held in the National Council meeting As the House would appreciate, this is a matter which would require very careful consideration before a final decision is taken

अध्यक्ष महोदय अब जो कुछ आप पूछना चाहते हैं उसको साफ करवा लीजिये । आप तो स्टेटमेंट पढने लगे ।

SHRI S M BANERJEE My question is this. 50,000 employees, who were temporary and who participated in the 19th September, 1968 strike were reinstated after the return of the Prime Minister from Latin